

उत्तराखंड के पोषक मोटे अनाजो का उपयोग करेगा कुपोषण को दूर

कृषि कुंभ (दिसंबर, 2022),
खण्ड 02 भाग 07, पृष्ठ संख्या 43-46

उत्तराखंड के पोषक मोटे अनाजो का उपयोग करेगा कुपोषण को दूर

अजय कुमार¹ व अरुण भट्ट²



¹वानिकी महाविद्यालय, वी0च0सिं0ग0 उत्तराखंड औद्यानिकी एवं
वानिकी विश्वविद्यालय, रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

²सह आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गोविन्द बल्लभ पंत
इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, एंड टेक्नोलॉजी, घुरदौड़ी, पौड़ी गढ़वाल,
उत्तराखंड भारत।

पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक प्रगति के बावजूद कुपोषण भारत में एक समस्या बना हुआ है। वैश्विक भूख सूचकांक (ग्लोबल हंगर इंडेक्स)-2017 के अनुसार भारत 119 देशों में 100 वें स्थान पर है जो की एक गंभीर चिंता का विषय है। कुपोषण को कम करने के लिए खाद्य व पोषण सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। धान और गेहूँ पर पोषण के लिए निर्भरता हमारी खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालता है। धान और गेहूँ को प्राथमिकता दिए जाने की वजह से कौनी और चीना का उत्पादन तो उत्तराखंड से लुप्त होता जा रहा है जबकि मंडुआ का रकबा 2006-07 में 10746 हे. की तुलना में 2016-17 में 9212 हे. हो गया है। इन फसलों के उत्पादन के घटने से एक बड़ी आबादी को कुपोषण का सामना करना पड़ रहा है। आज के समय में जहाँ अनाज की पर्याप्त उपलब्धता है वही सही पोषण न मिल पाना एक चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने और देश में उगाई जाने वाली कदन्न फसलों (पोषक मोटे अनाजो) को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाये जाने के भारत

सरकार के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृति दी गई है। इससे विश्व में पोषक अनाजों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और नई पीढ़ी भी पोषक अनाजों को अपने भोजन में शामिल करेंगी।

उत्तराखंड में कुपोषण की स्थिति

कुपोषण का मुख्य कारण भोजन व भोजन में पोषक तत्वों की कमी है। कुपोषण से सबसे ज्यादा महिलाये, बच्चे व युवा प्रभावित होते हैं। लडकियों व महिलाओं में खून की कमी (अनेमिया), बच्चों में नाटापन (सटनिंग), निर्बलता (व्यसटिंग), कम वजन जबकि युवाओं में अधिक वजन मुख्य लक्षण है। रास्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार वर्ष 2005-06 की तुलना में उत्तराखंड में अनीमिया, बच्चों में नाटापन और कम वजन की स्थिति में 2015-16 में थोडा सुधार हुआ है जबकि बच्चों में निर्बलता और युवाओं के अधिक वजन की समस्या 2005-06 की तुलना में 2015-16 में बढ़ी है (तालिका 9)।

तालिका (9): उत्तराखंड में कुपोषित महिलाये व बच्चों की स्थिति

कुपोषण	200506- (%)	2015-16 (%)	वृद्धि / कमी	स्रोत :Nutrition atlas
खून की कमी (anemia)	69.2	59.8	-9.4	
नाटापन (stunting)	39.6	33.5	-6.1	
निर्बलता(waisting)	18.2	19.5	1.3	
कम वजन(Underweight)	31.7	26.6	-5.1	
अधिक वजन (overweight)	11.4	17.7	6.3	

खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक

खाद्य सुरक्षा सुखा, प्रतिव्यक्ति कम आय, गरीबी, खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता, बीमारी, बदलता मौसम, पीने के पानी की कमी और महिलाओं व जनजातीय समूहों में पोषण को लेकर जानकारी का आभाव से मुख्यतः प्रभावित होती है।

कुपोषण को दूर करने में पोषक अनाजों का महत्त्व

पोषक अनाजों का कुपोषण को दूर करने में एक बड़ा योगदान हो सकता है। इन अनाजों में अधिक मात्रा में रेशा, कैल्शियम, आयरन और फॉस्फोरस पाया जाता है (तालिका 2)। इसमें गेहूँ व धान की तुलना में अधिक मात्रा में प्रोटीन व रेशा पाया जाता है। इनमें खनिज तत्व भी प्रचुरता में होते हैं जिससे कुपोषण की समस्या दूर होती है। यह पोषक अनाज आज के समय में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, थायरोइड, पेट से सम्बंधित बीमारियों व मोटापे से निपटने में सक्षम है पोषक अनाजों के आटे में ग्लूटन नहीं होता है अतः इसके उपयोग से पेट की समस्या नहीं होती है। यह अनाज पेट में धीरे धीरे पचते हैं जिसकी वजह से खून में तेजी से सुगर नहीं

बढ़ती है इसलिए आजकल डॉक्टर मधुमेह के रोगियों को चावल की जगह झंगोरे के चावल खाने की सलाह दे रहे हैं। पोषक अनाजों के उपयोग से न सिर्फ खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि गेहूँ व चावल पर निर्भरता भी कम होगी। अतः स्वस्थ जीवन के लिए इन पोषक अनाजों को अपने दैनिक भोजन में शामिल करने की जरूरत है।

पोषक अनाज उगाने से किसानों को लाभ

किसानों के लिए भी इन फसलों का उत्पादन लाभप्रद है क्योंकि जहाँ एक किलो मंडुआ या झंगोरे को उगाने में जहाँ 650-1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है वहीं एक किलो चावल उगाने में 5000 लीटर पानी लगता है अतः पर्यावरण को संरक्षित करने में भी इनकी अहम भूमिका हो सकती है। इनका उत्पादन मुख्यतः वर्षा आधारित क्षेत्रों में किया जाता है जबकि सिंचित क्षेत्रों में भी इनकी अधिक उपज कम लागत में ली जा सकती है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में चारे की समस्या रहती है और यह फसले पौष्टिक पशु चारा मुहैया करने में सक्षम है मोटे अनाजों में सूखे को सहने की क्षमता धान और गेहूँ की तुलना में अधिक होती है।

तालिका 2 : उत्तराखंड में पाए जाने वाले मोटे अनाज (पोषक अनाज) में चावल व गेहूँ की तुलना में पोषक तत्वों की मात्रा

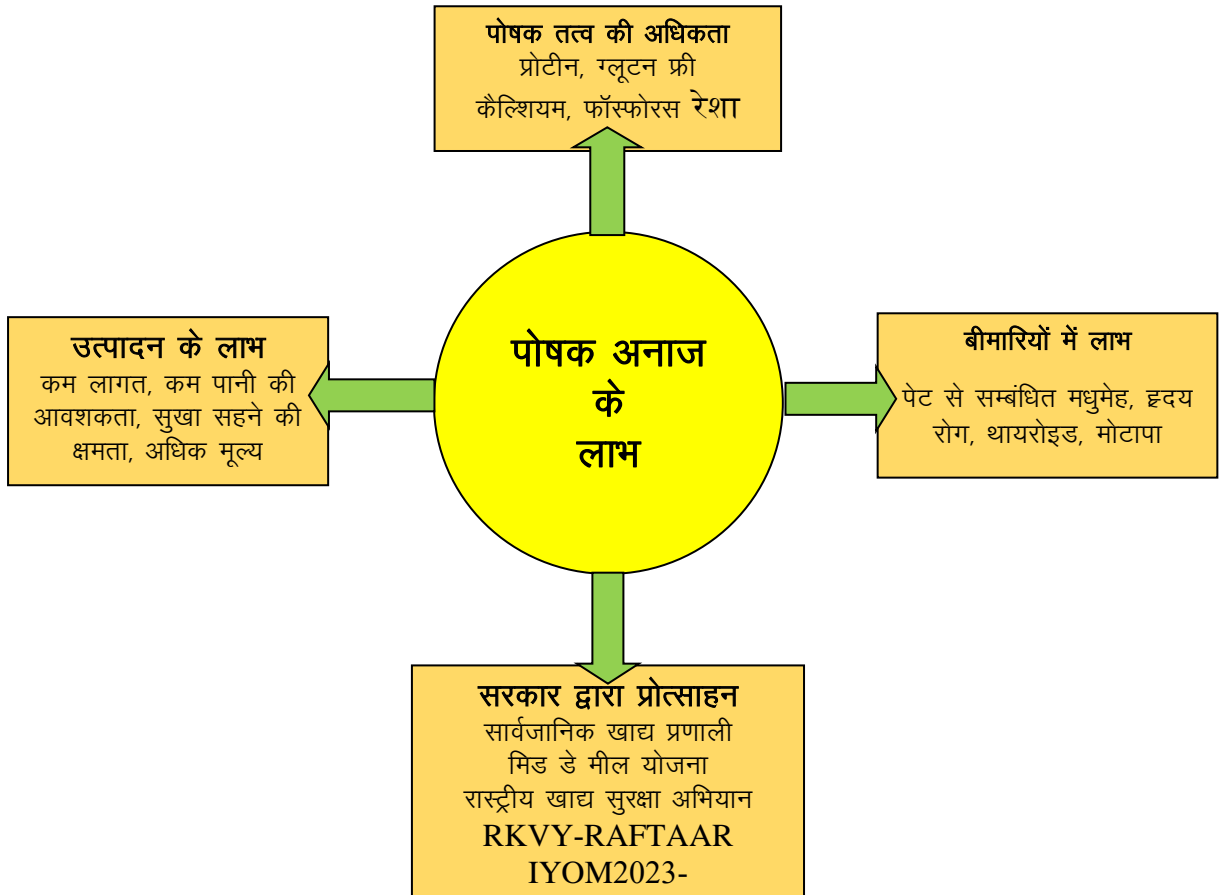
पोषक अनाज	प्रोटीन	रेशा	Ca	P	Fe	Mg	Na	K	Cu	Mn	Zn	थाईमिन	राइबोफ्लेविन	नियासिन
	(g/100g)		(mg/100g)											
मंडुआ (Finger Millet)	7.3	3.6	344	283	3.9	137	11	408	0.47	5.49	2.3	0.42	0.19	1.1
चीना (Proso millet)	12.5	2.2	8	206	2.9	114	5	195	0.8	1.6	1.7	0.41	2.8	4.5
कौणी (Foxtail millet)	12.3	8	31	290	2.8	143	1.3	364	0.59	1.16	3.51	0.59	0.11	3.2
झंगोरा (Barnyard Millet)	11.6	14.7	22	280	18.6	82	-	-	0.6	0.96	3	0.33	0.1	4.2
चवल (Rice)	6.8	0.2	10	160	0.5	32	6	130	0.25	1.1	1.2	0.41	0.0149	1.62
गेहूँ (Wheat)	11.8	1.2	41	306	3.9	120	3	363	0.9	13.3	1	0.41	5.46	5.5

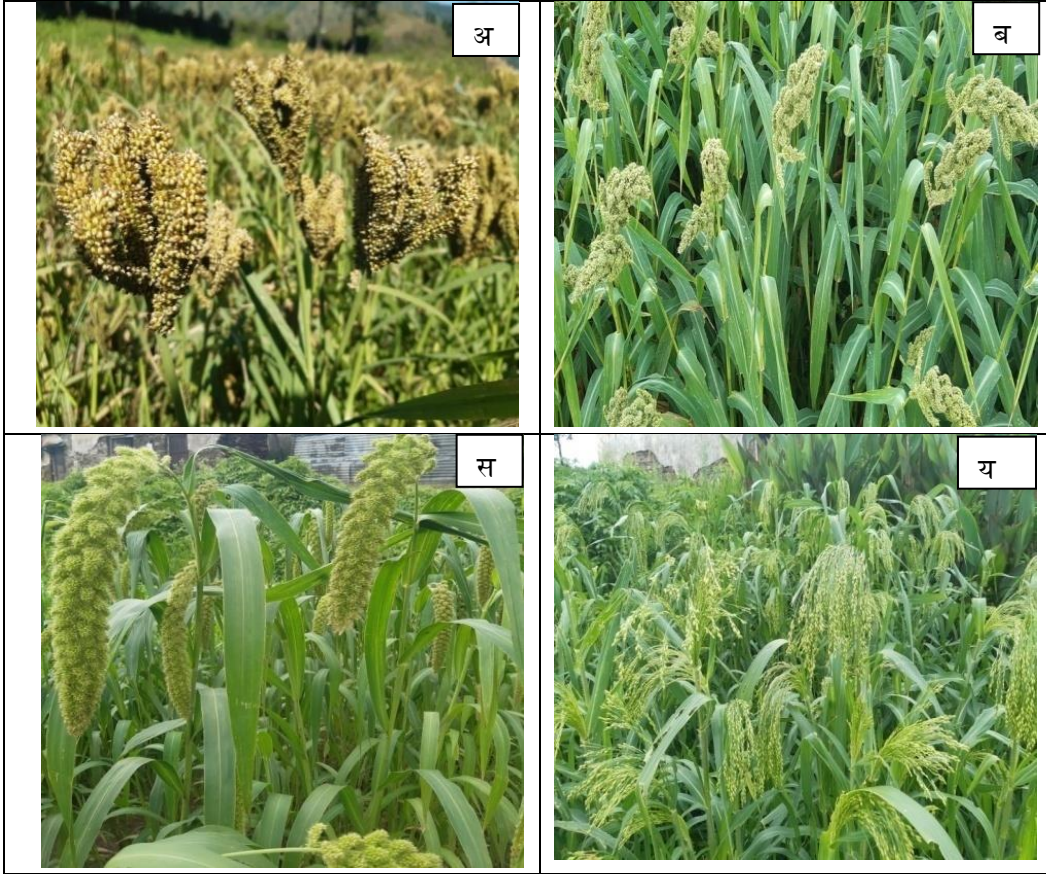
पोषक अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने से पानी की कमी और बढ़ते तापमान के कारण खाद्यान उत्पादन पर मंडराते संकट को दूर किया जा सकता है। पोषक अनाज के उत्पादन करने से विविधता पूर्ण खेती को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी साथ ही रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के इस्तेमाल में कमी आएगी। भारत सरकार द्वारा मंडुए के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 3578/- कुंतल घोषित किया है जो की धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 2040/- कुंतल की तुलना काफी अधिक है अतः छोटे एवं सीमांत किसानों की लिए भी इनका उत्पादन करना लाभकारी है।

पोषक अनाजों को बढ़ावा देने के लिये केंद्र सरकार व उत्तराखंड सरकार के प्रयास

पोषण, पारिस्थिकी व पर्यावरण के लिए लाभकारी होने की वजह से केंद्र व राज्य सरकारें इसके उपयोग व उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही हैं।

राज्य सरकारें सार्वजनिक खाद्य प्रणाली व मिड-डे मील में पोषक अनाजों को शामिल कर रही हैं जो बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पोषक अनाज उप-मिशन के माध्यम से मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने मोटा अनाज की खेती के लिए प्रेरित करने के लिए साल 2018 मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया था जबकि उत्तराखंड सरकार ने मंडुए, झंगोरे व अन्य पोषक अनाजों के उत्पादन और मांग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट महोत्सव दिसम्बर-2021 में मनाया। सरकार आर्गेनिक मंडुआ व झंगोरे को डेनमार्क व यूरोप के बाजार में निर्यात करने पर भी काम कर रही है। उत्तराखंड सरकार मंडुआ, झंगोरा, कौणी, चौलाई, कुट्टू आदि फसल किसानों से सीधे खरीदने की भी योजना चला रही है जिससे किसानों को इन फसलों का सही मूल्य मिल सके।





अ: मंडुआ, ब: झंगोरा, स: कौणी, य: चीना

यदि भारत को पोषक खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग से निपटना है तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में दूसरी हरित क्रांति जरूरी है। यह तभी संभव है जब कृषि शोध और मूल्य नीति मोटे अनाजों को केंद्र में रख कर बने। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार व किसानों के प्रयासों से मंडुआ, झंगोरा,

कौणी व चीना का उत्पादन व उपयोग बढ़ेगा। इन पौष्टिक अनाजों को बढ़ावा देने व भोजन में शामिल करने से कुपोषण, जैव विविधता व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से लड़ने में भी सहायक सिद्ध होंगी।

